

भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2474
उत्तर देने की तारीख 15 दिसंबर, 2025
सोमवार, 24 अग्रहायण, 1947 (शक)

पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र और कौशल विकास केंद्र

2474. श्री राजू बिष्टः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों (पीएमकेके) और कौशल विकास केंद्रों (एसडीसी) की जिला-वार संख्या कितनी है;
- (ख) 2019 से अब तक दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और उत्तरी दिनाजपुर जिलों में उक्त केंद्र और केंद्रों के लिए आवंटित निधि का वर्ष-वार ब्योरा क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में महिला उद्यमियों के लिए आरम्भ की गई और कार्यान्वित की गई कौशल विकास योजनाओं का जिला-वार ब्योरा क्या है; और
- (घ) उक्त जिलों में स्टार्ट-अप और उद्यम इकाइयों को प्रदान की गई सहायता का ब्योरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के द्वारा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल विकास केंद्रों द्वारा पश्चिम बंगाल सहित देश भर के सभी वर्गों, को कौशल, पुनर्कौशल एवं कौशलान्णयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौशल भारत मिशन (सिम) का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उन्हें उद्योग से संबंधित कौशलों से सुसज्जित करना है।

एमएसडीई की योजनाएं मांग आधारित हैं और इन योजनाओं के तहत प्रशिक्षण केंद्र आवश्यकतानुसार स्थापित या संचालित किए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में एमएसडीई की विविध योजनाओं के अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण केंद्रों (पीएमकेके सहित) का जिलावार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

एमएसडीई की किसी भी योजना के तहत जिलों को सीधे धनराशि जारी नहीं की जाती है। पीएमकेवीवाई और जेएसएस योजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण लागत को पूरा करने के लिए धनराशि जारी की जाती है। जेएसएस योजना के तहत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सीधे धनराशि जारी की जा रही है। एनएपीएस के तहत, प्रशिक्षुओं को, न कि इसके अंतर्गत आने वाले संस्थानों को, प्रति माह 1500 रुपये तक की वजीफा सहायता डीबीटी के माध्यम से जारी की जाती है। आईटीआई से संबंधित दैनिक प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के पास होता है।

पश्चिम बंगाल में एमएसडीई की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जारी की गई धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है:

	राशि करोड़ रुपए में	
	जेएसएस (2018-19 से 31.10.2025 तक)	एनएपीएस (2018-19 से 31.10.2025 तक)
पीएमकेवीवाई (2015-16 से 31.10.2025)	27.61	84.37
427.26		

(ग) और (घ): एमएसडीई अपने स्वायत्त संस्थानों, अर्थात् राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड), नोएडा और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी के माध्यम से पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी) और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) आयोजित करता है। पश्चिम बंगाल में वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक निस्बड नोएडा द्वारा प्रशिक्षित महिला उद्यमियों का जिलावार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, समावेशी उद्यमशीलता इको सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए उद्यमिता शिक्षा, प्रशिक्षण और समर्थन के माध्यम से भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल सहित पूरे भारत में निम्नलिखित पहल की है:

(i) उद्यमिता प्रोत्साहन हेतु योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम; एमएसई-क्लस्टर विकास कार्यक्रम; पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि योजना; नवाचार, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना; स्टार्टअप इंडिया; स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम; प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन; प्रौद्योगिकी इंक्यूबेशन एवं उद्यमी विकास योजना, आदि।

(ii) देश में नवाचार, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और स्टार्टअप इको सिस्टम में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत इको सिस्टम बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने जनवरी 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की। प्रमुख योजनाएं, जैसे कि फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स (सीजीएसएस), स्टार्टअप्स को उनके व्यावसायिक चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करती हैं।

(iii) इसके अलावा, युवाओं को व्यावसायिक उद्यम या स्टार्टअप स्थापित करने के लिए क्रेडिट / ऋण तक पहुंच प्रदान करने हेतु, सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड-अप इंडिया आदि जैसी विभिन्न योजनाएं लागू करती है।

इसके साथ ही, एमएसडीई ने स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कौशल संवर्धन के लिए एक व्यापक और सुलभ मंच है, जो देश के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल पाठ्यक्रम, रोजगार के अवसर और उद्यमिता सहायता प्रदान करता है। प्रशिक्षित उम्मीदवारों की जानकारी सिद्ध पोर्टल पर उपलब्ध है, जिससे वे संभावित नियोक्ताओं से जुड़ सकते हैं। सिद्ध के माध्यम से उम्मीदवार रोजगार और प्रशिक्षण के अवसरों तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में प्रमाणित उम्मीदवारों को रोजगार और शिक्षता के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार मेले और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षता मेले (पीएमएनएएम) आयोजित किए गए हैं।

पश्चिम बंगाल में पीएमकेके और एसडीसी ' के संबंध में दिनांक 15.12.2025 को उत्तरार्थ लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2474 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पश्चिम बंगाल एमएसडीई की विभिन्न योजनाओं के तहत जिलावार प्रशिक्षण केंद्र

ज़िला	पीएमकेवीवाई 4.0 केंद्र	पीएमकेके	जेएसएस केंद्र	एनएपीए स प्रतिष्ठान	सीटीएस	
					सरकारी आईटीआई	निजी आईटीआई
परगना उत्तर 24	29	7	1	224	11	13
परगना 24 दक्षिण	33	3	1	91	12	8
अलीपुरद्वार	2	1	-	30	1	0
बांकुड़ा	6	1	1	27	11	10
बीरभूम	7	2	-	86	11	7
कूचबिहार	6	1	-	30	5	0
दार्जिलिंग	9	1	-	95	6	2
दिनाजपुर दक्षिण	6	1	-	30	7	0
दिनाजपुर उत्तर	5	1	-	24	6	1
हुगली	14	4	-	99	9	15
हावड़ा	10	2	1	171	6	5
जलपाईगुड़ी	9	1	1	59	7	1
झारग्राम	4	-	-	10	2	0
कलिम्पोंग	2	-	-	11	1	0
कोलकाता	12	2	-	580	5	3
मालदा	5	2	-	56	6	1
मेदिनीपुर पूर्व	14	2	1	176	3	15
मेदिनीपुर पश्चिम	10	3	1	85	13	14
मुर्शिदाबाद	17	2	-	71	8	6
नदिया	14	3	-	74	13	12
पश्चिम बर्धमान	9	2	-	99	2	0
पूर्व बर्धमान	19	1	-	72	16	26
पुरुलिया	8	1	1	28	7	10
कुल	250	43	8	2228	168	149

पश्चिम बंगाल में 2022-23 से 2024-25 तक निस्बड नोएडा द्वारा प्रशिक्षित महिला उद्यमियों का जिलावार ब्यौरा

ज़िला	महिला प्रतिभागियों की संख्या
24 परगना उत्तर	154
अलीपुरद्वार	67
बांकुड़ा	92
बीरभूम	45
दिनाजपुर दक्षिण	157
हावड़ा	148
कोलकाता	443
मुर्शिदाबाद	49
नादिया	105
पूर्व बर्धमान	85
पुरुलिया	49
कुल	1,394
